से नजर रखती है जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। पूरी रक्षा तयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू कर दिए गए हैं।

गंगा नदी के जल को प्रदूषण रहित बनाये रखने के लिए किए गए प्रयास

396. **श्री राम जेटमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के जल को प्रदूषण रहित बनाये रखने हेतु पिछले कुछ वर्षों में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपायों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन उपायों से प्राप्त परिणामों की समीक्षा की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के तीन राज्यों के लिए 281.50 करोड़ रुपये की लागत पर 262 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। ये स्कीमें अवरोधन, दिशा-परिवर्तन, म्युनिसिपल अपशिष्ट जल के दिशा-परिवर्तन और उपचार, अल्प-लागत स्वच्छता; विद्युत शवदाहगृह की स्थापना एवं नदी तटाग्र की सुविधाओं के बारे में हैं। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रण भी किया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गंगा कार्य योजना पर 159.68 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) गंगा कार्य योजना की प्रगति एवं परिणामों की प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 147 स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 47 अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीमों के पूरा हो जाने के फलस्वरूप अनुमानतः प्रतिदिन 329 मिलियन लीटर म्युनिसिपल अपशिष्ट जल को अभी तक नदी में प्रवाहित होने से रोका जा सका है। उपर्युक्त के अलावा पांच सीवरेज उपचार संयंत्रों, 13 विद्युत शवदाहगृहों और 12 नदी तटाग्र सुविधाओं को भी पूरा किया जा चुका है। गंगा कार्य योजना में अल्प-लागत स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2727 सामुदायिक शौचालयों एवं 40529 निजी शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करना

397. **श्री राम जेटमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1990 के टाइम्स आफ इण्डिया में "इकोनोमिक पैनल अनहैप्पी विद जाब प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आर्थिक सलाहकार परिषद ने योजना आयोग द्वारा सुझाई गयी रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने वाली नीति का समर्थन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए तैयार की गयी योजना की रूप रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोबर्धन) : (क) जी, हां। सरकार को प्रश्न में उल्लिखित समाचार की जानकारी है।

(ख) आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा "1990 के दशक में विकास के लिए रोजगारोन्मुख कार्यनीति विकसित करने की दिशा में" शीर्षक अंतरिम रिपोर्ट में